सांध्य दैनिक
4PM
जिद...सच की
www.4pm.co.in www.facebook.com/4pmnewsnetwork @Editor_Sanjay YouTube @4pm NEWS NETWORK
● वर्ष: 9 ● अंक: 96 ● पृष्ठ: 8 ● लखनऊ, गुरुवार, 11 मई, 2023
मूल्य ₹ 3/-

जो छोटी-छोटी बातों में सच को गंभीरता से नहीं लेता है, उस पर बड़े मसलों में भी भरोसा नहीं किया जा सकता।
-अल्बर्ट आइंस्टीन

पाकिस्तान के बेकाबू हालात पर सतर्क... 2 | जातिगत जनगणना पर रोक से... 3 | शहर की सरकार चुनने निकले लोग... 7

सुप्रीम टिप्पणी : उद्धव इस्तीफा नहीं देते तो सरकार होती बहाल

» शिवसेना के 16 बागी विधायकों के मामले पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई

» मामला वृहद पीठ को सौंपा

» विधायक ले सकते हैं विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। शिवसेना के 16 बागी विधायकों के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणियां की हैं। सबसे बड़ी टिप्पणी उद्धव ठाकरे के बारे में है। देश के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ ने कहा कि उद्धव ठाकरे को फ्लोर टेस्ट का सामना करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने साथ ही कहा कि अगर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो महाराष्ट्र में उनकी सरकार को बहाल किया जा सकता था।

बेंच की इस टिप्पणी के बाद साफ है कि उद्धव ठाकरे अगर इस्तीफा देने की जल्दबाजी नहीं करते तो वह महाराष्ट्र के दोबारा सीएम बन सकते थे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मामला वृहद पीठ को सौंप दिया है। विधायकों के पास विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने का अधिकार होगा।

राज्यपाल व विस अध्यक्ष की भूमिका पर सवाल

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राज्यपाल के पास ऐसा कोई संचार नहीं था जिससे यह संकेत मिले कि असंतुष्ट विधायक सरकार से समर्थन वापस लेना चाहते हैं। इसके बावजूद विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया गया। तत्कालीन राज्यपाल ने शिंदे गुट के 34 विधायकों के अनुरोध पर फ्लोर टेस्ट कराने के निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि फ्लोर टेस्ट कराने का उनका फैसला सही नहीं था क्योंकि राज्यपाल के पास इस निष्कर्ष पर पहुंचने का कोई ठोस आधार नहीं था कि उद्धव ठाकरे बहुमत खो चुके हैं। यथास्थिति को इसलिए नहीं बदला जा सकता क्योंकि सबसे बड़े दल यानी भाजपा के समर्थन से एकनाथ शिंदे को शपथ दिलाकर राज्यपाल ने न्यायोचित काम किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर यह मान भी लिया जाए कि विधायक राज्यपाल राजनीति के मैदान में आकर पार्टी के अंदरूनी या बाहरी विवाद को सुलझाने की भूमिका नहीं निभा सकते। वे सिर्फ इस आधार पर फैसला नहीं ले सकते थे कि कुछ सदस्य शिवसेना को छोड़ना चाहते हैं। राज्यपाल की तरफ से विवेकाधिकार का इस्तेमाल संविधान के अनुरूप नहीं था। राज्यपाल को पत्र पर भरोसा करना चाहिए था। उस पत्र में यह कहीं नहीं कहा गया था कि ठाकरे ज्यादातर विधायकों का समर्थन खो चुके हैं। विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका पर भी सख्त टिप्पणी की है।

शिवसेना शिंदे गुट का व्हिप अवैध : राउत

दरअसल, संजय राउत ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शिंदे गुट का व्हिप गैरकानूनी है। इसका मतलब है कि उनका व्हिप गैरकानूनी है और इसके मुताबिक सबकी (शिंदे गुट) सदस्यता निरस्त हो जाएगी। राउत ने आगे कहा कि मौजूदा सरकार गैरकानूनी है और संविधान के खिलाफ बनाई गई है। उद्धव गुट के नेता अनिल परब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं थी वह फिर से अध्यक्ष के पास जाएंगी लेकिन मुख्य सचेतक सुनील प्रभु होंगे क्योंकि दूसरे मुख्य सचेतक को अयोग्य ठहराया गया है इसका मतलब है कि जो व्हिप सुनील प्रभु ने जारी किया था जिसका उल्लंघन हुआ है वह रिकॉर्ड पर है और इसकी जल्द सुनवाई होगी और इन लोगों (शिंदे गुट) की सदस्यता निरस्त होगी।

पागल हो गए राउत : शेवाले

शिवसेना सांसद राहुल शेवाले ने राउत को पागल बताया। उन्होंने कहा कि संजय पागल हो गए हैं। और पागल आदमी पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। उन्हें पागल आदमी जैसे बोलने दो।

बेंच बोली : फ्लोर टेस्ट का सामना करते उद्धव

सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने कहा कि उद्धव ठाकरे को विधानसभा में बहुमत परीक्षण का सामना करना चाहिए था। उद्धव ठाकरे ने अगर इस्तीफा नहीं दिया होता तो सरकार बहाल की जा सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही कहा कि व्हिप का फैसला पार्टी को ही करना चाहिए। इसके लिए विधायकों की संख्या काफी नहीं है। सिर्फ विधायक तय नहीं कर सकते कि व्हिप कौन होगा। व्हिप को पार्टी से अलग करना ठीक नहीं होगा। इसके साथ ही पार्टी में असंतोष फ्लोर टेस्ट का आधार नहीं हो सकता है।

दिल्ली सरकार को 'सुप्रीम' राहत

एलजी को झटका

बड़ा फैसला : ट्रांसफर, पोस्टिंग का अधिकार सरकार के पास

» प्रशासन के कामों में उपराज्यपाल को माननी पड़ेगी सलाह

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर लंबे समय चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की पीठ ने अपना फैसला सुना दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह सर्वसम्मति का फैसला है। बता दें, इस पीठ के अन्य सदस्य जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा है। राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण से संबंधित दिल्ली सरकार की याचिका पर पीठ ने फैसला सुनाया है।

सुप्रीम कोर्ट ने 18 जनवरी को आदेश रखा था सुरक्षित

पीठ ने केंद्र और दिल्ली सरकार की ओर से क्रमशः सालिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की पांच दिन दलीलें सुनने के बाद 18 जनवरी को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। संविधान पीठ का गठन दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर केंद्र और दिल्ली सरकार की विधायी एवं कार्यकारी शक्तियों के दायरे से जुड़े कानूनी मुद्दे की सुनवाई के लिए किया गया था। पिछले साल छह मई को शीर्ष कोर्ट ने इस मुद्दे को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेज दिया था।

चुनी हुई सरकार की जवाबदेही प्रभावित न हो : सीजेआई

सीजेआई ने कहा कि अगर एक चुनी हुई सरकार को अपने अधिकारियों को नियंत्रित करने का अधिकार नहीं होगा तो इससे जवाबदेही के सिद्धांतों की कड़ी अनावश्यक साबित हो जाएगी। इसलिए ट्रांसफर, पोस्टिंग का अधिकार सरकार के पास रहेगा। वहीं, प्रशासन के कामों में एलजी को सरकार की सलाह माननी चाहिए। गौरतलब है, संविधान पीठ का गठन दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर केंद्र और दिल्ली सरकार की विधायी एवं कार्यकारी शक्तियों के दायरे से जुड़े कानूनी मुद्दे की सुनवाई के लिए किया गया था। पिछले साल छह मई को शीर्ष कोर्ट ने इस मुद्दे को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेज दिया था।

पाकिस्तान के बेकाबू हालात पर सतर्क रहे भारत : फारूक

» बोले- अस्थिरता सभी के लिए खतरनाक

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अस्थिर पाकिस्तान भारत समेत सभी देशों के लिए खतरनाक है। उनकी यह टिप्पणी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान को भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद आई है। नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष ने कहा, अस्थिर पाकिस्तान हमारे देश सहित अन्य सभी देशों के लिए खतरनाक है।

हम एक मजबूत और लोकतांत्रिक पाकिस्तान चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आंतरिक स्थिति बहुत खतरनाक है। आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब है। उन्होंने कहा, वहां पिछले साल बाढ़ आई थी। कई इलाके अभी भी प्रभावित हैं। वहां के लोग अभी भी पीड़ित हैं। पड़ोसी देश में स्थिति खतरनाक है, लेकिन इस तरह की घटनाओं का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा, अगर आप पाकिस्तान का इतिहास देखें तो पहले पीएम की हत्या हुई, फिर जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। उनकी बेटी बेनजीर भुट्टो को गोली मार दी गई। अब इमरान खान चौथे पूर्व पीएम हैं, जिन्हें जेल भेज दिया गया है। उधर, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को कहा कि राजनीतिक नेताओं को तुच्छ आरोपों पर गिरफ्तार किए जाने से पाकिस्तान का लोकतंत्र खतरे में है। पूर्व मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी इमरान खान को गिरफ्तार किए जाने के बाद आई है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान में लोकतंत्र तार-तार हो गया है।

लोकतंत्र पर खतरा बना हुआ है : महबूबा मुफ्ती

जम्मू। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री एवं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भारतीय मीडिया और अदालत पर सवाल उठाए हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पाकिस्तान में राजनीतिक नेताओं को तुच्छ आरोपों पर गिरफ्तार किया जा रहा है। वहां लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन, उम्मीद की किरण ये है कि वहां की स्वतंत्र न्यायपालिका और मीडिया सरकार को जवाबदेह ठहरा रहे हैं। जोकि भारत के मीडिया और अदालत से विपरीत है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, पाकिस्तान में लोकतंत्र पर खतरा बना हुआ है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र (भारत) के विपरीत वहां एकमात्र उम्मीद की किरण एक स्वतंत्र न्यायापालिका और सरकार को जवाबदेह ठहराने वाला मीडिया है। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मंगलवार को गिरफ्तार किए जाने के बाद आई है। 70 वर्षीय खान को अर्धसैनिक रेंजर्स ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय से भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के समर्थकों ने देशभर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया है।

तमिलनाडु मंत्रिमंडल में फेरबदल

» पलानीवेल की जगह थंगम थेनारासु संभालेंगे वित्त विभाग

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

चेन्नई। तमिलनाडु के मंत्री पलानीवेल थियागा राजन को गुरुवार को वित्त और मानव संसाधन प्रबंधन के प्रमुख मंत्रालय से मुक्त कर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग दिया गया। थंगम थेनारासु नए वित्त मंत्री हैं और उनके द्वारा आयोजित उद्योग पोर्टफोलियो को मन्नारगुडी निर्वाचन क्षेत्र से तीन बार के विधायक टीआरबी राजा को आवंटित किया गया था, जिन्हें नए मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया था।

राजभवन की एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि पीटीआर के रूप में संबोधित थियागा राजन आईटी और डिजिटल सेवा विभाग को संभालेंगे। आईटी विभाग का पोर्टफोलियो पहले टी मनो थंगराज द्वारा संभाला जाता था और अब उन्हें दूध और डेयरी विकास विभाग सौंपा गया है। एसएम नसर, जिनके पास दूध विभाग था, को 9 मई को मंत्रिमंडल से हटा दिया गया था। ये सारे विभाग मुख्यमंत्री स्टालिन की सहमति से बांटे गये है।

भाजपा एक झूठ बोलने वाली पार्टी : पीसी शर्मा

» मैंने अपने समय में 23 से ज्यादा तीर्थ यात्रा कराई

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

भोपाल। मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता पीसी शर्मा ने भाजपा को जमकर कोसा है। मैंने 23 से ज्यादा यात्रा कराई, बीजेपी झूठ बोलती हैं। उन्होंने कहा हमारी सरकार थी तो हमने कोई तीर्थयात्रा बंद नहीं कराई, मैंने 23 से ज्यादा यात्रा कराई। भोपाल दक्षिण-पश्चिम विधानसभा सीट से विधायक पीसी शर्मा की मानें तो कमलनाथ सरकार में उन्हें मंत्री पद मिला था, इसके बावजूद वह 18-18 घंटे काम करते थे। अपने विधानसभा क्षेत्र में हमेशा सक्रिय रहते थे। उनका प्रदर्शन ही उनके लिए जीत की गारंटी है।

पीसी शर्मा दूसरी बार के विधायक हैं। 1994 से 1998 तक भोपाल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे। 1998 में पहली बार विधानसभा चुनाव जीता और 2018 में दूसरी बार। कमलनाथ सरकार में जनसंपर्क, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विमानन, विधि एवं विधायी कार्य एवं अध्यात्म विभागों के मंत्री का दायित्व भी संभाला। मैं जनता के बीच का नेता हूं। मंत्री था तब भी 18 घंटे काम करता था। कोरोना काल में लोगों की हरसंभव मदद करने के लिए 24 घंटे काम किया। मैं धर्मस्व मंत्री था, तब 23 से ज्यादा धार्मिक यात्राएं कराई। हमने कुंभ, पटियाला साहिब की यात्रा पर भेजा। बुजुर्गों के साथ युवाओं और बच्चों को भी जाने की अनुमति दी।

विधायक की मां को गाली देना ठीक नहीं

» आप सांसद संजय सिंह ने सपा विधायक का किया समर्थन

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

अमेठी। अमेठी के गौरीगंज में सपा विधायक व उनके समर्थकों द्वारा भाजपा नेता दीपक सिंह की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। भाजपा ने सपा नेता व उसके समर्थकों पर गुंडई करने का आरोप लगाया है। इस पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह के समर्थन में ट्वीट किया है।

उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पहले भाजपाईयों ने सपा विधायक के मामा के लड़के राहुल और कई लोगों को मारा उन पर एफआईआर के लिए विधायक थाने में बैठे थे। भाजपा नेता की हिम्मत देखिये थाने में आकर विधायक को गाली दी। राजनीति अपनी जगह है लेकिन क्या थाने में एक विधायक को मां बहन की गाली देना ठीक है? क्या किसी भाजपा विधायक को कोई मां की गाली देगा तो वो चुप रहेगा।वीडियो वायरल होने पर सपा विधायक ने भी बयान दिया है। सपा विधायक ने कहा कि भाजपा नेता दीपक सिंह बीते चार दिनों से मेरे परिजनों और समर्थकों के पीछे पड़े हैं। कई जगहों पर मेरे समर्थकों को पीटा और उन्हें गौरीगंज में नजर न आने की हिदायत भी दी। गौरीगंज में चार दिन से गुंडागर्दी चल रही थी। उसने मेरे भाई और भतीजे पर हमला किया था। रात भर मैं थाने में बैठा रहा पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

राजस्थान में कांग्रेस-भाजपा में मिलीभगत : पालीवाल

जयपुर। आम आदमी पार्टी राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल ने कहा कि नाथद्वारा में पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री गहलोत ने मंच साझा करते हुए एक दूसरे की पीठ थपथपाई। यह बीजेपी-कांग्रेस की मिलीभगत को सबसे बड़ा सबूत है। प्रदेश अध्यक्ष पालीवाल ने कहा कि पहले तो दोनों नेताओं ने एक साथ मंच साझा किया और बाद में जनता में सही साबित होने की कोशिश भी की। इससे एक बार फिर से साबित हो गया है कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि एक तरफ पीएम मोदी कह रहे हैं कि कुछ लोग देश में अच्छा होते हुए देखना नहीं चाहते। दूसरी तरफ पीएम खुद को मुख्यमंत्री का मित्र बताते हैं। अगर पीएम मोदी को लगता है कि देश में कांग्रेस विकास कार्यों में अड़चने पैदा कर रही है, तो यह मित्रता क्या कहलाती है? नवीन पालीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ये दो तरफा खेल अब नहीं चलेगा, देश और राजस्थान की जनता सब समझ चुकी है, इसलिए चुनावी मौसम में इधर-उधर की बातें न करके मुद्दों की बात करो।

मुंबई में शरद-उद्धव से मिलेंगे नीतीश कुमार

» बिहार सीएम के स्वागत में मुंबई में लगे पोस्टर

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

पटना। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना विपक्षी एकता का मिशन और तेज कर दिया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार की सुबह शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मिलने मुंबई रवाना हो गए। जानकारी के अनुसार, नीतीश कुमार विपक्षी एकता का संदेश लेकर मुंबई गए हैं।

उनके साथ उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, बिहार विधान परिषद के सभापति देवेशचंद्र ठाकुर और सहकारिता मंत्री संजय कुमार झा भी मुंबई रवाना हुए हैं। वहीं, मुंबई में जदयू की ओर से नीतीश कुमार का जोरदार स्वागत करने की तैयारी है। मुंबई में जगह-जगह देश मांगे नीतीश के पोस्टर नजर आ रहे हैं। इन पोस्टर पर नीतीश कुमार के सहर्ष स्वागत की बात लिखी है। कहा जा रहा है कि अगर, विपक्षी दल भाजपा के खिलाफ एकजुट होते हैं तो नीतीश कुमार को नेतृत्व सौंपा जा सकता है। ऐसे में जदयू अभी से नीतीश कुमार को विपक्षी दलों का नेता बनाने में जुटा है। इधर, नीतीश कुमार के मुंबई दौरे को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा तेज है। नीतीश मुंबई में उद्धव ठाकरे और शरद पवार से विपक्षी एकजुटता को लेकर विमर्श करेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एकजुट करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। वे विपक्ष के नेताओं से घूम-घूमकर मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने बुधवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी। दोनों की मुलाकात सकरात्मक बताई जा रही है।

सोरेन से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि वे लोग मिलजुल कर आगे बढ़ते रहेंगे। एकजुट होकर देश को बनाने में योगदान करेंगे। झारखंड और देश के विकास के लिए काम करेंगे। इधर, हेमंत सोरेन ने नीतीश को अपना अभिभावक बताया है।वहीं, दो दिन पहले बिहार के सीएम ओडिशा दौरे पर थे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात की थी। हालांकि, दोनों ने किसी भी राजनैतिक मुद्दे पर बातचीत से इनकार किया था। नीतीश कुमार ने कहा कि उनके नवीन पटनायक से संबंध अच्छे है। इसलिए मिलने आए हैं।

पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे नवीन पटनायक

वहीं, ओडिशा के सीएम गुरुवार को पीएम मोदी से मिलने दिल्ली रवाना होंगे। अब नीतीश कुमार से मुलाकात के दो दिन बाद नवीन पटनायक का दिल्ली पहुंचना भी चर्चा का विषय बन गया है। बताया जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पटनायक और पीएम मोदी में बात हो सकती है।

जाति जो कभी जाती नहीं

जातिगत जनगणना पर रोक से नाराज नीतीश सरकर

» वोट मांगने का बनते आधार

» नेता व राजनीति के लिए जाजिव धर्म जरूरी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

पटना। कहते है जाति वो है जो जाती नहीं है। भारत में जातियों को नजर अंदाज करना मुश्किल है। सामाजिक व्यवस्था से लेकर राजनैतिक व्यवस्था तक इससे प्रभावित होती है। भारतीय राजनीति हो या चुनाव, इनमें जातियों का बड़ा महत्व होता है। राजनीतिक पार्टिया या नेता जब कहते हैं कि हम जातियों को इकट्ठा कर रहे हैं तो हक़ीक़त में वे उन्हें बाँट रहे होते हैं। धर्म, जाति और समुदायों को बाँटने का यह सिलसिला अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है।

जब जरूरत पड़ती है, इन्हें ठोक-पीटकर एक कर लिया जाता है और ज़रूरत के अनुसार ही इन्हें फिर से बांटने में सारी ऊर्जा झोंक दी जाती है। आजकल ऐसा ममाला बिहार का चल रहा है। नीतीश कुमार की सरकार वहाँ जातीय जनगणना करवा रही है। आने वाली 15 मई को यह काम पूरा होने वाला था। गुरुवार यानी 4 मई को हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। अब कम से कम अगली सुनवाई तक सरकार जनगणना के आँकड़ों को सार्वजनिक नहीं कर सकती। हाईकोर्ट का कहना है कि जनगणना का काम केंद्र सरकार का है। राज्य यह तभी करवा सकता है जब विधानसभा में इस आशय का कानून पारित किया जाए।

बिहार की राजनीति के लिए भी जरूरी है गणना

मुझे लगता है कि इस मामले में सरकार ने अगर कानून विशेषज्ञों का सहारा लिया होता तो ऐसी फजीहत नहीं होती। यह गणना बिहार ही नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति के लिए भी जरूरी मानी जा रही है। यह इतना ही जरूरी मुद्दा है कि विधानसभा में जब इस विधेयक को लाया गया तो इसका सर्वसम्मति से समर्थन किया गया। पक्ष-विपक्ष के तमाम नेताओं ने इसका दिल खोलकर स्वागत किया। हालांकि इस मामले में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के विचारों में अंतरविरोध दिखा। एक तरफ केंद्र की भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर बताया कि केंद्र जाति आधारित जनगणना नहीं कराएगा तो दूसरी तरफ बिहार में भाजपा जतीय जनगणना के पक्ष में विरोधी नेताओं के सुर में सुर मिलाती रही। बिहार भाजपा आज भी जातीय गणना के समर्थन में है और बिहार सरकार पर होईकोर्ट में अपना पक्ष ठीक से नहीं रखने का आरोप लगाया है। हालांकि अन्य दलों ने भी सरकार पर विफलता का ठप्पा लगाने की कोशिश की है। सभी दल जातीय गणना से हासिल होने वाले आंकड़ों की आंच में अपनी-अपनी रोटी सेंकने का सपना संजो रहे हैं। इन आंकड़ों से समाज के शोषितों-वंचितों का कितना भला होगा यह तो वक्त बताएगा लेकिन इतना तो तय है कि आने वाले दिनों में बिहार में अगड़ा-पिछड़ा की राजनीति जोर पकड़ेगी। मंडल-कमंडल का भी डंका बजेगा। हालांकि इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं आया है। इसे अंतरिम रोक बताया गया है। अगली सुनवाई तीन जुलाई को होगी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि तीन जुलाई को इस मामले में हाईकोर्ट की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है। लेकिन चार मई को जातीय गणना पर अंतरिम रोक लगाते हुए हाईकोर्ट ने जो प्रतिक्र या दी, वह काफी गंभीर थी। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया हमारी राय है कि राज्य के पास जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की कोई शक्ति नहीं है। जिस तरह से यह किया जा रहा है, वह एक जनगणना के समान है। ऐसा करना संघ की विधायी शक्ति पर अतिक्रमण होगा। जाति आधारित गणना के दौरान बिहार सरकार ने चालाकी से बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की। सरकार ने इसे जातीण जनगणना नहीं कहा, बल्कि इसका नाम जाति आधारित गणना दिया गया। कोर्ट को यह बताया कि यह जाति आधारित सर्वेक्षण है। लोगों ने वही समझा जो सरकार समझाना चाहती थी। हाईकोर्ट में सरकार की यह चालाकी पकड़ी गई। विभिन्न संस्थाओं और कुछ व्यक्तियों द्वारा दायर की गई याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि राज्य एक सर्वेक्षण की आड़ में एक जातिगत जनगणना करने का प्रयास नहीं कर सकता। खासकर जब राज्य के पास बिल्कुल विधायी क्षमता नहीं है और उस स्थिति में न ही भारत के संविधान की धारा 162 के तहत एक कार्यकारी आदेश को बनाए रखा जा सकता है। अपनी महत्वपूर्ण टिप्पणी में हाईकोर्ट ने सर्वेक्षण और जनगणना के बीच के अंतर को भी बिल्कुल साफ शब्दों में रेखांकित किया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जनगणना सटीक तथ्यों और सत्यापन योग्य विवरणों के संग्रह पर विचार करता है। जबकि सर्वेक्षण का उद्देश्य आम जनता की राय और धारणाओं का संग्रह और उनका विश्लेषण करना है। सर्वेक्षण में ज्यादातर तार्किक निष्कर्ष होते हैं। राज्य द्वारा वर्तमान कवायद को केवल सर्वेक्षण के नाम पर जनगणना करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

नीतीश कुमार ने फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया

मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि सर्वसम्मति इसे सदन से पास किया गया था। इसमें सबकी गिनती के साथ-साथ आर्थिक स्थिति का भी पता लगाया जाना है, चाहे वह किसी भी जाति का हो वा किसी भी समुदाय का। उन्होंने कहा है कि हम लोग सबके हित में यह काम कर रहे हैं। पता नहीं क्यों इसका विरोध हो रहा है। इससे तो पता चलता है कि लोगों को मौलिक चीजों की समझ नहीं है।दूसरी ओर बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इस मामले में भाजपा से चिढ़े हुए हैं और अभी भी आशान्वित हैं। उनका कहना है कि आज न कल जातिगत गणना जरूर होगी। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इस मामले में सरकार की मंशा पर ही सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार जाति आधारित गणना करवाना ही नहीं चाहती थी। जिस कारण जानबूझकर ऐसा करवाया गया।

फिलहाल सवाल यह भी है कि अगर अंतिम रूप से इस पर रोक लग जाती है तो इस मामले में अभी तक जो समय, श्रम और संसाधन का दुरुपयोग हुआ है, उसकी जवाबदेही कौन लेगा? बिहार की सत्ता की बागडोर लंबे दिनों से उन्हीं लोगों के हाथ में है जिन लोगों ने समाजवाद का दामन पकड़कर अपना राजनीतिक चेहरा चमकाया था। लालू हों या नीतीश सबकी पहचान समाजवाद से जुड़ी है लेकिन उनके यहाँ, उनकी पार्टियों में समाजवाद की क्या स्थिति है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। असल में उनकी पार्टियों में अब समाजवाद नहीं, सामंतवाद का बोलबाला है। अगर उनके यहां समाजवाद होता तो आज राजद की बागडोर तेजस्वी के हाथों में नहीं होती।

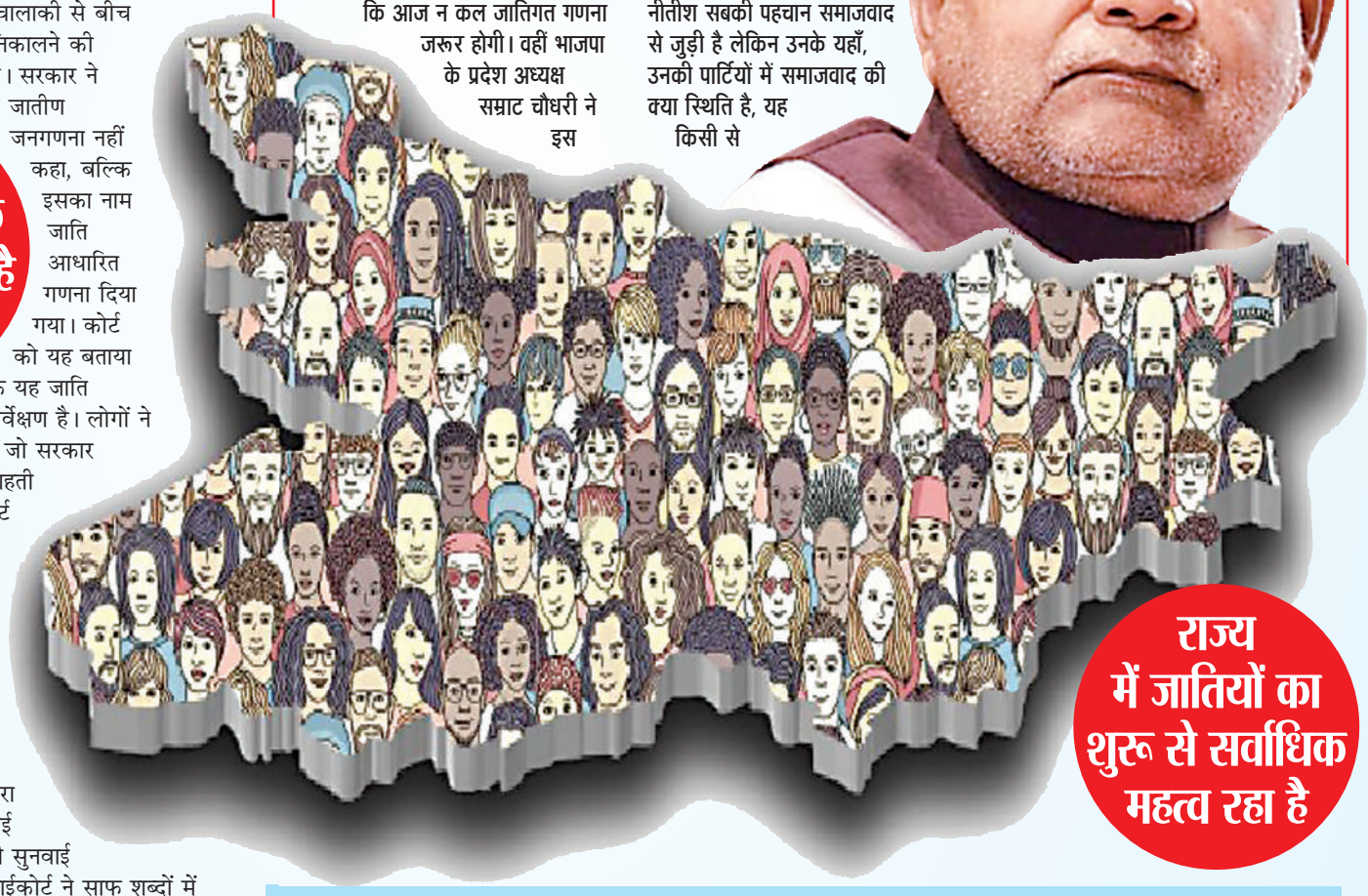

राज्य में जातियों का शुरू से सर्वाधिक महत्व रहा है

राहुल ने भी उठाया था जातिगत गणना की बात

दरअसल, बिहार में जातियों का शुरू से सर्वाधिक महत्व रहा है। लम्बे समय से यहाँ माँग चल रही है कि जिस जाति का जितना हिस्सा जनसंख्या में है, उसे उतनी ही मात्रा में आरक्षण दिया जाए। पिछले दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी यह माँग उठाई थी और कहा था- जिसका जितना हिस्सा, उसकी उतनी भागीदारी तय हो। कुल मिलाकर बिहार में सारा मामला अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) को लेकर चल रहा है। पिछली जनगणना के अनुसार बिहार में ओबीसी और ईबीसी की हिस्सेदारी 55प्रतिशत थी। कई सर्वे में बाद में यह दावा किया गया कि 2011 के बाद इस प्रतिशत में काफ़ी वृद्धि हो चुकी है। जदयू और राजद का दावा है कि बिहार में ओबीसी और ईबीसी की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत से भी अधिक हो चुकी है। 2024 में राजद और जदयू इसे भुनाना चाहते हैं। पिछड़े वर्ग का कहना है कि जब अनुसूचित जाति-जनजाति (एससी- एसटी) को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है तो पिछड़ा वर्ग के लिए भी यही आधार क्यों नहीं माना जाता? नीतीश सरकार पिछड़े वर्ग के साथ न्याय करना चाहती है। राजद और जदयू का सबसे बड़ा वोट बैंक भी यही वर्ग है। हाईकोर्ट की रोक से सरकार या ये कहें कि जदयू और राजद आहत हैं। हालाँकि आँकड़े तो अब सरकार के पास आ ही गए होंगे। रोक के कारण वह इन्हें सार्वजनिक नहीं कर सकती। यही सबसे बड़ी अड़चन है। जब तक आँकड़े सार्वजनिक नहीं होते, इन्हें वोट में परिवर्तित करने में परेशानी आएगी। अगर ओबीसी वाक़ई सत्तर प्रतिशत हो गए हैं तो यह उन्हें बताया जाएगा और यह भी कि अब उनकी इस संख्या के आधार पर ही उनके साथ न्याय किया जाएगा, तभी तो प्रभाव पड़ेगा! इस बीच ओडिशा में भी जातीय जनगणना शुरू हो चुकी है। वहाँ की सरकार भी इसके पीछे गरीबों और पिछड़ों के प्रति न्याय का भाव देख रही है।

जिद... सच की

Sanjay Sharma
editor.sanjaysharma
@Editor_Sanjay

पाकिस्तान में बवाल भारत की नजर

पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद देशभर में गृहयुद्ध जैसे हालात हो गए हैं। दो बड़े प्रांतों पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सेना को हालात पर काबू करने के लिए बुलाया गया है। इमरान खान समर्थकों ने पाकिस्तानी सेना के रावलपिंडी स्थित मुख्यालय पर भी हमला बोला दिया था। पाकिस्तानी सेना के कई कोर कमांडरों के ठिकानों को भी जला दिया गया है।

भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में हालात दो दिन से बेकाबू हो गए हैं। पूर्व पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हिंसात्मक उत्पात मचा कर परे देश को गृहयुद्ध में धकेल दिया है। वहां की उथलपुथल का असर भारत पर भी पड़ सकता है। भारत वहां की स्थिति पर नजर रखे हुए है। ज्ञात हो कि पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद देशभर में गृहयुद्ध जैसे हालात हो गए हैं। दो बड़े प्रांतों पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सेना को हालात पर काबू करने के लिए बुलाया गया है। इमरान खान समर्थकों ने पाकिस्तानी सेना के रावलपिंडी स्थित मुख्यालय पर भी हमला बोला दिया था। पाकिस्तानी सेना के कई कोर कमांडरों के ठिकानों को भी जला दिया गया है। इस खतरनाक हालात के बीच पाकिस्तान के परमाणु बमों की सुरक्षा को लेकर आशंका जताई जाने लगी है। कराची, लाहौर, पेशावर, सियालकोट और तमाम शहरों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुखिया इमरान के समर्थक हिंसा कर रहे हैं।

यह डर तब और बढ़ जाता है जब उन जगहों पर भी हिंसा होती है जहां पर परमाणु हथियार रखे हुए हैं। आइए जानते हैं कि पाकिस्तान के किन इलाकों में परमाणु बमों का जखीरा रखा हुआ है।हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास इस समय 165 परमाणु हथियार हैं। साल 2016 में इनकी संख्या 130 से 140 थी। इसी साल अमेरिकी रिपोर्ट में बताया गया था कि ये परमाणु हथियार कहां-कहां रखे हुए हैं। कुछ अमेरिकी वैज्ञानिकों के एक ग्रुप ने इस रिपोर्ट को तैयार किया था। इसे कुछ सैटेलाइट तस्वीरों की मदद से बनाया गया था। इसके मुताबिक कराची के मसरूस एयर बेस के पश्चिम में परमाणु हथियारों को बड़ा जखीरा मौजूद है। यहां पर इन हथियारों को अंडरग्राउंड करके रखा गया है। साथ ही यहां पर भारी सुरक्षाबल भी तैनात रहता है। माना जा रहा है कि अंडरग्राउंड सेंटर हो सकता है कि कमांड सेंटर हो। जिन वैज्ञानिकों ने इस रिपोर्ट को तैयार किया था वो फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स से जुड़े हुए थे।। संस्था के टॉप वैज्ञानिक हैं, एम क्रिस्टेंसन ने कहा था सैटेलाइट से जो तस्वीरें मिली हैं, उन्हें देखने के बाद कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में कम से कम पांच जगहें ऐसी हैं जहां पर परमाणु हथियार रखे गए हैं। हैंस ने जिन जगहों के नाम लिए थे उसमें सिंध का एक्रो, पंजाब का गुजरांवाला, बलूचिस्तान का खुजदार, सिंध का ही पानो अकील और सरगोधा स्थित आर्मी कैंट का नाम था। बहावलपुर में एक छठा बेस भी तैयार किया जा रहा है। इन हालातों को देखते हुए अब विश्व समुदाया को भी हस्तक्षेप करने की जरूरत है।

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

नये कानून पर भरोसा कायम करना ही समाधान

प्रमोद भार्गव

पूर्वोत्तर के सातों राज्यों में अक्सर हिंसा की वजहें बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ, बिगड़ता जनसंख्यात्मक घनत्व, संसाधनों पर अतिक्रमण और अर्द्धसैनिक बलों का विरोध रही हैं। लेकिन यह अपवाद है कि कानूनी असमानता के चलते हिंसा का ऐसा तांडव हो गया कि 54 लोग काल के गाल में समा गए और 150 से ज्यादा घायल हैं। वहीं अपनी नाकामी पर पर्दा डालते हुए मणिपुर सरकार कह रही है कि लोग गलतफहमी का शिकार होकर हिंसा में लिप्त हो गए। लेकिन सवाल उठता है कि संदेह उत्पन्न क्यों हुआ और हो भी गया था तो उसको सुलझाने के प्रभावी प्रयत्न क्यों नहीं हुए। दरअसल मणिपुर उच्च न्यायालय ने इसी माह एक आदेश जारी किया कि सरकार मैतेई आदिवासी समुदाय के लोगों को आदिवासी समुदाय की श्रेणी में शामिल करने पर विचार करे। लेकिन सरकार यदि यह समझ लेती कि ऐसे मुद्दे सरकारी नौकरी और सुविधाओं का लाभ लेने से जुड़े हैं, इसलिए चिंगारी सुलगते ही विस्फोट की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। ताजा हिंसा इसी नसमझी का दुष्परिणाम है।

गत फरवरी माह में राज्य सरकार ने पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों से अवैध प्रवासियों को बाहर करने की शुरुआत कर दी थी। इन क्षेत्रों की नगा और कूकी समुदाय की 33 जातियां, जनजाति की श्रेणी में अधिसूचित हैं। अतएव इनके लिए चिन्हित भूभाग पर किसी गैर-जनजातीय समुदाय के लोग काबिज नहीं हो सकते हैं। विडंबना देखिए जिन लोगों को प्रवासी बताकर विस्थापन का सिलसिला शुरू किया गया उन्हें इस इलाके के मूल निवासी कूकी समुदाय ने अपना बताया। किंतु सरकार ने इस तथ्य पर ध्यान न देते हुए कूकियों की बेदखली का सिलसिला तो बनाए ही रखा, साथ ही मैतेई समुदाय को जब जनजाति का दर्जा मिल गया, तब उन्हें नगा और कूकी समुदाय के लोगों को आरक्षित भूखंडों पर भी काबिज होने से नहीं रोका। विवाद की असली जड़ यही विरोधाभास रहा। मैतेई समुदाय इस इलाके में आर्थिक और राजनीतिक रूप से सक्षम वर्ग है। संख्याबल में भी वे अधिक हैं व मणिपुर विधानसभा की 60 में से 40 सीटों पर काबिज हैं।

जबकि पहाड़ी इलाकों के 90 प्रतिशत दुर्गम भू-भाग में रहने वाली नगा और कूकी जनजातियों के केवल 20 विधायक ही हैं। ज्यादातर मैतेई हिंदू हैं। जबकि नगा और कूकियों में से 90 फीसदी धर्मांतरित ईसाई हैं। ऐसे में यह विवाद आसानी से धार्मिक रंग में बदलकर हिंसक हो गया। यूं भी इन हालातों के निर्माण की प्रक्रिया तभी शुरू

हो गई थी, जब विधानसभा से 2015 में तीन नये विधेयक पारित हुए थे। इन कानूनों को स्थानीय जनजातीय समुदायों ने व्यापक हितों के प्रतिकूल मान लिया था। इन विधेयकों से आदिवासी समूहों में आशंकाएं गहरी हुई कि बाहरी लोगों को पर्वतांचलों का स्थाई निवासी बनाये जाने के रास्ते इन कानूनों के जरिये खोले जा रहे हैं। इसीलिए यह मामला बाहरी बनाम मूल निवासियों की जंग में उलझकर विस्फोटक हो गया है। जो कानून भेद को और बढ़ाने का शक पैदा करे तो विरोध के स्वर तो मुखर होंगे ही। विवाद व हिंसक आंदोलन का कारण 'यात्री किरायेदार एवं प्रवासी नियमन विधेयक-2015' बना हुआ है। इस विधेयक में इनर लाइन परमिट हासिल करने के तरीके को कड़ा किया गया है। यह मांग जीसीआरएलपीएस संगठन ने उठाई थी कि मणिपुर में बाहरी लोगों की संख्या और हस्तक्षेप लगातार बढ़ रहा है। इसे नियंत्रित किया जाए। मूल रूप से यह मांग मणिपुर के बहुसंख्यक मैतेई समुदाय की थी। इसका विरोध आदिवासी समुदाय शुरुआत से कर रहे हैं। उन्हें भय है कि अगर ये कानून अमल में आ जाते हैं तो उन्हें जो 'मणिपुर घाटी जन-प्रशासन नियमन अधिनियम 1947 के तहत विशेष अधिकार मिले हुए हैं, उनका हनन होगा। नये कानून के अनुसार 1951 के पहले से मणिपुर में रह रहे अथवा पलायन करके आये प्रवासी ही मणिपुर में रह सकेंगे। मसलन 1951 के बाद बसने वाले प्रवासियों को राज्य के नागरिकों को दी जाने वाली सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी, दूसरे जरूरत महसूस होने पर सरकार उन्हें राज्य से बेदखल भी कर सकती है। यानी 1951 के पहले आ गए घुसपैठियों को भी मणिपुर की आदिवासियों के लिए आरक्षित की गई पहाड़ी ग्रामों में भी संपत्ति खरीदने व रोजगार हासिल करने के अधिकार प्राप्त हो जाएंगे।

मैतेई समुदाय भी जनजातियों की तरह मणिपुर का हजारों साल से इस इलाके के मूल निवासी है। वे इस कानून को बनाए रखने और उस पर अमल करने की मांग इसलिए कर रहे हैं, जिससे बांग्लादेश, तिब्बत और म्यांमार के घुसपैठियों का मणिपुरवासियों के आजीविका के संसाधनों पर कब्जा न होने पाए। मणिपुर उच्च न्यायालय का आदेश इसी विधेयक से सामने आये कानून को अमल में लाने से संबंधित है। इस विधेयक के पारित होते ही हिंसा भड़की। अब राज्य सरकार का दायित्व बनता है कि वह भड़के लोगों के कानून की वास्तविक इबारत से परिचित कराए और जान-माल की सुरक्षा की गारंटी ले।

सेहत पर भारी है खाना जो बाजारी

देविंदर शर्मा

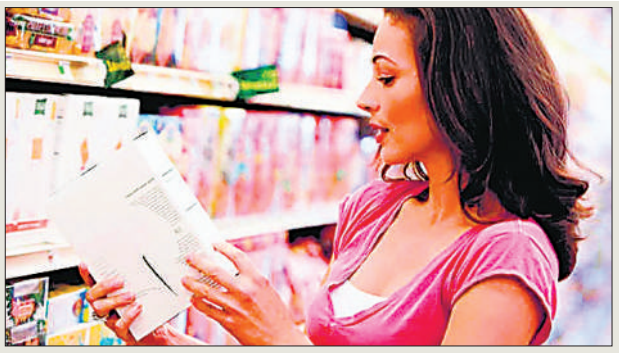

स्वयं मधुमेह का रोगी होने के कारण एक नियम बना रखा है कि खाने-पीने की कोई वस्तु खरीदने से पहले लेबल में दी जानकारी पढ़ता हूं। जाहिर है, सबसे पहले यही देखता हूं कि चीनी कितनी मिलाई गई है। इसका अर्थ यह कि सुपर-मार्किट में रखे जूस, शरबत, माल्ट आधारित पेय, प्रसंस्कृत अनाज जैसे कि दलिया या ओट्स, चॉकलेट, टॉफियां और सुगंधित दही इत्यादि पदार्थ- जिनमें चीनी काफी मात्रा में मिलाई होती है- यह सब मेरे लिए अछूत हैं। धीरे-धीरे खाद्य पदार्थ में मौजूद उन अवयवों की जानकारी को लेकर कुछ और जिज्ञासु होने लगा हूं, जिनके बारे में अधिक जानकारी नहीं। मेरी सदा यही कोशिश रहती है कि अपेक्षाकृत कम बाहरी अवयव और प्रिजर्वेटिव मिलाए खाद्य वस्तुएं ही खरीदूं।

आजकल सुपरमार्किटों की शेल्फें परम-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों और पेय के पैकटों से लदी पड़ी होती हैं। मुझे अभी भी यह पक्का नहीं है कि यह प्रयास मुझे मधुमेह के दुष्प्रभावों से बचाने में कितने मददगार रहे हैं, लेकिन समझता हूं कि किसी सामान्य उपभोक्ता से कुछ अधिक जानकार रहने से फर्क तो पड़ता ही है। तथ्य है कि अमेरिका में प्रचलित खाद्य वस्तुओं में लगभग 73 फीसदी वह हैं जो परम-प्रसंस्कृत श्रेणी में आती हैं और यूरोप में यह आंकड़ा करीबन 60 प्रतिशत है। जरा-सी अधिक सावधानी बरतने से उपभोक्ता को काफी फायदा हो सकता है। यू-ट्यूब पर बहुत-सी वीडियो बताती हैं कि चीनी हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी घातक है, यहां तक कि चीनी को छद्म नाम देकर मिलाया जा रहा है। लेकिन पहले यह जान लेते हैं कि परम प्रसंस्कृत खाद्य असल में है क्या। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के एक ब्लॉग में इसकी परिभाषा बताई गई है 'ज्यादातर यह खाद्य उत्पाद अलग से मिलाए अवयव, जैसे कि चीनी, नमक, वसा, स्टार्च, कृत्रिम रंग, प्रिजर्वेटिव्स आदि मिलाकर बनाए जाते हैं।'

सुपरमार्किट में मिलने वाली अधिकांश वस्तुओं में इनमें कुछ अवयव तो जरूर होते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि पैकेट की चमक-दमक और लुभावनेपन से वशीभूत होकर खरीदारी करने से पहले लेबल पढ़ने की आदत डालें। आखिरकार अध्ययन बताते हैं कि परम-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के सेवन में महज 10 फीसदी की बढ़ोतरी होने से स्तन कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी तरह, ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल का संबंध थॉइरॉयड बीमारी की प्रत्येक किस्म से जोड़ा जाता है। जो लोग कुछ अधिक जानना चाहते हैं, उन्हें 'ट्रू-फूड टेक' नामक वेबसाइट पर उपलब्ध डाटाबेस से विस्तृत जानकारी पाने का सुझाव देना चाहूंगा। वहां पर अमेरिकी बाजार में प्रचलित खाद्य उत्पादों के 50000 से ज्यादा वस्तुओं का लेखाजोखा दिया हुआ है। किसी उत्पाद को बनाने के दौरान प्रसंस्करण कितने स्तर पर हुआ है, आप इसका तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। आपको कौन-सी खाद्य वस्तु चुननी चाहिए, वहां पर दी जानकारी वास्तव में एक मार्गदर्शक बन सकती है। अब यदि आप कहें कि यह डाटाबेस तो अमेरिका का है, तो बताना चाहूंगा कि इनमें बहुत से उत्पाद भारत में भी आयात होते हैं या फिर इनके भारतीय प्रतिरूप बनकर बिक रहे हैं, यानी हमारे यहां भी उतना ही परम-प्रसंस्करण किया जा रहा है। जो भी है, यह डाटाबेस किसी खाद्य वस्तु के लेबल पर तकनीकी शब्दों में दी जानकारी का असल अर्थ जानने में सहायक है।

यहां मुझे स्वास्थ्य मार्गदर्शक और सोशल मीडिया पर काफी प्रभाव रखने वाले रेवंत हिमतसिंगका और बहुराष्ट्रीय एवं महाकाय कैडबरी के बीच हुआ हालिया विवाद याद आ रहा है। रेवंत ने कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में कैडबरी के लोकप्रिय उत्पादन बोर्नविटा के स्वास्थ्य-वर्धन संबंधी दावों की बखिया उधेड़ दीं। यह पोस्ट सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली और अकेले इंस्टाग्राम पर ही 1.2 करोड़ लोगों ने इसको देखा। बाद में इसको ट्विटर और लिंक्ड-इन जैसे सोशल मंचों पर भी साझा किया गया। लेकिन जब रेवंत को कैडबरी की ओर से बड़े वकीलों वाली फर्म का कानूनी नोटिस मिला तो उन्होंने उक्त पोस्ट्स हटा लीं और कंपनी से सार्वजनिक माफी भी मांग ली। इस बाबत रेवंत ने कहा 'मैं उक्त वीडियो बनाने के लिए कैडबरी से माफी मांगता हूं। मेरी योजना या नीयत किसी भी ट्रेडमार्क या कंपनी को बदनाम करने की नहीं थी।' ठीक है उन्हें यह करना पड़ा, लेकिन सोशल मीडिया पर 'फूड फार्मर' नामक साइट चलाने वाले रेवंत के लिए एक बहुराष्ट्रीय खाद्य कंपनी से बिना शर्त माफी मांगना क्या वाकई सही है। यह विवाद यहीं खत्म नहीं हो जाता। आखिरकार, कोई शख्स कानून-सेवा देने वाली किसी बड़ी कंपनी से लंबे खिंचने वाले मुकदमे में क्यों उलझना चाहेगा। डिलीट की वीडियो में रेवंत ने दिखाया था 'उनकी 100 ग्रा. बोर्नविटा सामग्री में 50 ग्रा. तो चीनी है। मूलत:, आधा भाग केवल चीनी है।'

हालांकि कैडबरी का रटा-रटाया जवाब था 'बोर्नविटा वैज्ञानिक ढंग से तैयार एक यौगिक है, जिसके घटक उपयोग के लिए मान्यता प्राप्त हैं और सभी अवयव पैकेट के लेबल में दर्शाए गए हैं।' रेवंत की पोस्ट के बाद मीडिया पर एक तगड़ी बहस छिड़ गई। मुझे खुशी है कि मीडिया की अनेकानेक हस्तियों, बहुत से मेडिकल डॉक्टर और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोगों ने कैडबरी कंपनी द्वारा एक शख्स को कानूनी हथकंडों से चुप कराने के ढंग की भर्त्सना की है, जबकि वे इस तथाकथित शक्तिप्रदाता पेय के बारे में बृहद जागरूकता बना रहे थे।

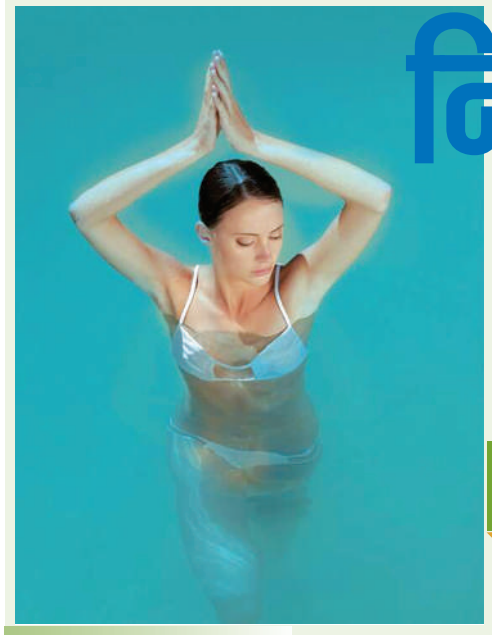

नियमित योगा से कम होगा वजन

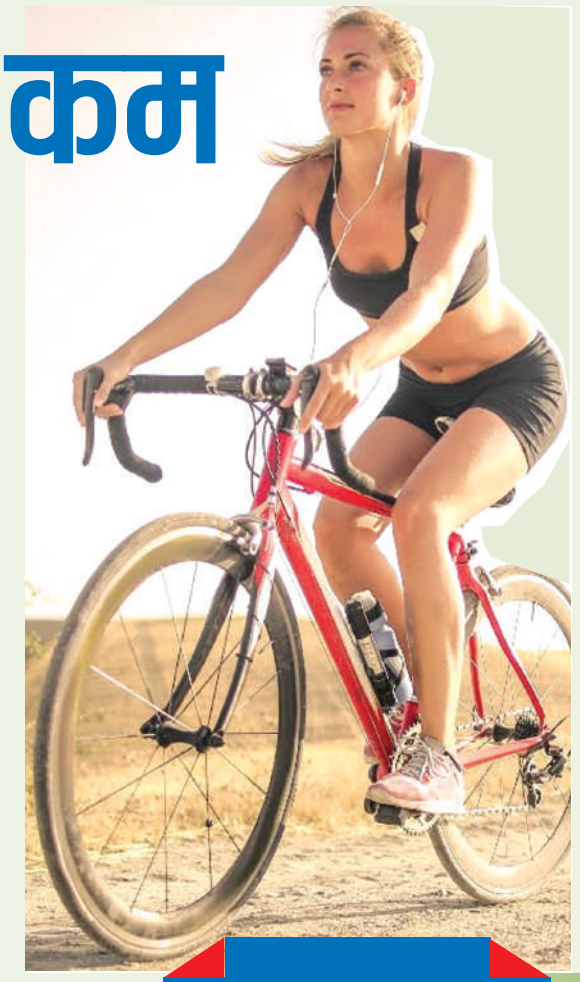

स्वस्थ रहने के लिए वजन को नियंत्रित रखना आवश्यक है। बढ़ा हुआ वजन कई बीमारियों को आमंत्रण देता है। शरीर में अतिरिक्त वसा होने से मोटापा या वजन बढ़ जाता है। वजन बढ़ने की एक वजह गलत खान-पान और बिगड़ी लाइफस्टाइल हैं। ऐसे में वेट लॉस करने के लिए लोगों को अपने खान पान और लाइफस्टाइल में बदलाव करने की जरूरत होती है। इसके साथ ही कई तरीकों से लोग वजन कम कर सकते हैं। सबसे जरूरी है शरीर को एक्टिव रखना। रोजाना सुबह की एक्सरसाइज या योग वजन कम करने में फायदेमंद हैं। इसके लिए लोग जिम में घंटों पसीना बहाते हैं। लेकिन गर्मियों में वजन कम करने में मेहनत लगती है। कभी कभी अधिक एक्सरसाइज करने या पसीना बहाने से डिहाइड्रेशन हो सकता है। गर्मियों में शरीर में पानी की कमी हो जाती है और कई गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में अगर आप गर्मी के मौसम में वजन कम करना चाहते हैं तो अपने वर्कआउट रूटीन में बदलाव करें। हैवी एक्सरसाइज करने के बजाए कुछ ऐसे व्यायाम करें जो अधिक तापमान में आसानी से किए जा सकते हैं।

करें वॉटर योगा

गर्मियों में व्यायाम करने का एक बेहतर विकल्प है वॉटर योग। वॉटर योग शरीर और मन को तनाव मुक्त रखता है। मांसपेशियों में दर्द की शिकायत को कम करने के साथ ही मानसिक आराम भी देता है। ऐसे में गर्मी के मौसम में आप वॉटर योग करके भी वजन घटा सकते हैं।

तैराकी करना

स्विमिंग एक अच्छा व्यायाम है। तैराकी के दौरान आपके दोनों हाथ और पैर गतिशील रहते हैं। इस कारण आपका फुल बॉडी वर्कआउट होता है। गर्मियों में नियमित स्विमिंग करें। एक घंटा स्विमिंग करने से 400 कैलोरी बर्न होती है और शरीर को बेहतर शेप मिलता है। वजन कम करने के लिए रोजाना स्विमिंग करें और स्विमिंग करते समय अलग अलग तरह के वेरिएशन अपनाएं।

पैदल चलना

रोजाना मात्र थोड़ी दूर पैदल चलकर भी अपने वजन घटा सकते हैं। गर्मियों में मॉर्निंग वॉक के लिए निकलें। शाम को भी वॉक कर सकते हैं। किसी पार्क में पेड़ पौधों की ठंडी हवा के बीच पैदल चलने से कैलोरी भी बर्न होगी और गर्मी भी कम लगेगी। इसके अलावा अगर आप पहाड़ों के आसपास रहते हैं तो ट्रैकिंग पर जा सकते हैं।

योगाभ्यास करें

वजन कम करने के लिए योग का नियमित अभ्यास भी फायदेमंद है। योग कई तरह की बीमारियों से बचाता है और शरीर को स्वस्थ रखता है। योग मुद्राएं, श्वास और ध्यान तकनीकों का अभ्यास करें। घर से बाहर हैं तो स्टैंडिंग योगा कर सकते हैं।

साइकिल चलाना

वजन कम करने के लिए कैलोरी बर्न करनी होती है। इसके लिए साइकिल चलाना एक बेहतर विकल्प है। नियमित रूप से साइकिल चलाने से मांसपेशियां मजबूत होती है और अच्छे से काम करती हैं। साइकिल चलाने के लिए तड़के सुबह या शाम को धूप जाने के बाद का समय चुनें। इससे आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और अधिक गर्मी भी महसूस नहीं होगी।

हंसना मना है

भिखारी- एक अदमी मुझसे पूछ रहा था कि मैं कितना कमा लेता हूं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बोला और चुप रहा। दूसरा भिखारी- ऐसा क्यों? भिखारी- मुझे शक था कि कहीं ये इनकम टैक्स वाला तो नहीं है।

पति (मरते समय अपनी बीवी से)- अलमारी से तेरे सोने के गहने मैंने ही चोरी किए थे, बीवी रोते हुए- कोई बात नहीं जी पति- तेरे भाई ने तुझे जो एक लाख रुपये दिए थे, वो भी मैंने ही गायब किए थे, पत्नी- कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ किया, पति- तेरी कीमती साड़ियां भी मैंने ही चोरी कर अपनी प्रेमिका को दे दिए थे, पत्नी- कोई बात नहीं जी, आपको जहर भी तो मैंने ही दिया था, अब आप आराम से मर जाइए...!

पत्नी- देखो मौसम कितना हसीन है, तुम्हारा क्या प्लान है? पति- मेरा तो वही है 178 में 1 GB का 28 दिन के लिए। पत्नी- घुस जाओ तुम मोबाइल में पहले...

पत्नी- काश मैं न्यूज पेपर होती, कम से कम तुम रोज मुझे हाथों में तो लेतें। पति- मैं ही यही सोचता काश तुम न्यूज पेपर होती, तो मुझे रोज नयी तो मिलती।

कहानी | गौरैया और घमंडी हाथी

एक पेड़ पर एक चिड़िया अपने पति के साथ रहा करती थी। चिड़िया सारा दिन अपने घोंसले में बैठकर अपने अंडे सेती रहती थी और उसका पति दोनों के लिए खाने का इंतजाम करता था। वो दोनों बहुत खुश थे और अंडे से बच्चों के निकलने का इंतजार कर रहे थे। एक दिन चिड़िया का पति दाने की तलाश में अपने घोंसलें से दूर गया हुआ था और चिड़िया अपने अंडों की देखभाल कर रही थी। तभी वहां एक हाथी मदमस्त चाल चलते हुए आया और पेड़ की शाखाओं को तोड़ने लगा। हाथी ने चिड़िया का घोंसला गिरा दिया, जिससे उसके सारे अंडे फूट गए। चिड़िया को बहुत दुख हुआ। उसे हाथी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जब चिड़िया का पति वापस आया, तो उसने देखा कि चिड़िया हाथी द्वारा तोड़ी गई शाखा पर बैठी रो रही है। चिड़िया ने पूरी घटना अपने पति को बताई, जिसे सुनकर उसके पति को भी बहुत दुख हुआ। उन दोनों ने घमंडी हाथी को सबक सिखाने का निर्णय लिया। वो दोनों अपने एक दोस्त कठफोड़वा के पास गए और उसे सारी बात बताई। कठफोड़वा बोला कि हाथी को सबक मिलना ही चाहिए। कठफोड़वा के दो दोस्त और थे, जिनमें से एक मधुमक्खी थी और एक मेंढक था। उन तीनों ने मिलकर हाथी को सबक सिखाने की योजना बनाई, जो चिड़िया को बहुत पसंद आई। अपनी योजना के तहत सबसे पहले मधुमक्खी ने हाथी के कान में गुनगुनाना शुरू किया। हाथी जब मधुमक्खी की मधुर आवाज में खो गया, तो कठफोड़वे ने आकर हाथी की दोनों आखें फोड़ दी। हाथी दर्द के मारे चिल्लाने लगा और तभी मेंढक अपने परिवार के साथ आया और एक दलदल के पास टर्रटराने लगा। हाथी को लगा कि यहां पास में कोई तालाब होगा। वह पानी पीना चाहता था, इसलिए दलदल में जाकर फंसा। इस तरह चिड़िया ने मधुमक्खी, कठफोड़वा और मेंढक की मदद से हाथी से बदला ले लिया।

7 अंतर खोजें

जानिए कैसा रहेगा कल का दिन

पंडित संदीप आत्रेय शास्त्री

लेखक प्रसिद्ध ज्योतिषविद हैं। सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कॉल करें-9837081951

मेष भूमि व भवन की खरीद-फरोख्त लाभदायक रहेगी। उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। कुसंगति से बचें। कारोबार में वृद्धि होगी। निवेशादि शुभ रहेंगे। रोजगार में वृद्धि होगी।

वृषभ अध्यात्म में रुचि रहेगी। किसी धार्मिक आयोजन में भाग लेने का मौका हाथ आएगा। सुख-शांति बने रहेंगे। कारोबार मनोनुकूल चलेगा। मित्रों का सहयोग लाभ में वृद्धि करेगा।

मिथुन रचनात्मक कार्य सफल रहेंगे। किसी आनंदोत्सव में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। प्रसन्नता तथा मनोरंजन के साधन उपलब्ध होंगे। कारोबार लाभदायक रहेगा।

कर्क बुरी खबर प्राप्त हो सकती है। मेहनत अधिक होगी। लाभ के अवसर टलेंगे। समय पर बाहर से धन नहीं मिलने से निराशा रहेगी। हल्की हंसी-मजाक करने से बचें।

सिंह सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। घर-बाहर पूछ-परख रहेगी। व्यापार-व्यवसाय मनोनुकूल लाभ देगा। धन प्राप्ति सुगम होगी। लाभ के अवसर हाथ आएंगे।

कन्या पुराने साथियों तथा रिश्तेदारों से मुलाकात सुखद रहेगी। अच्छे समाचार प्राप्त होंगे। मान बढ़ेगा। किसी नए उपक्रम को प्रारंभ करने पर विचार होगा।

तुला कारोबार से लाभ होगा। निवेश में जल्दबाजी न करें। आय बनी रहेगी। थकान व कमजोरी रह सकती है। अज्ञात भय रहेगा। अनहोनी की आशंका रहेगी।

वृश्चिक फालतू खर्च होगा। शत्रुओं से सावधानी आवश्यक है। स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहेगा। कोई भी निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें। वाणी पर नियंत्रण रखें।

धनु डूबी हुई रकम प्राप्त हो सकती है। यात्रा मनोनुकूल रहेगी। नए काम हाथ में आएंगे। कारोबारी वृद्धि से प्रसन्नता रहेगी। समय की अनुकूलता का लाभ लें।

मकर योजना फलीभूत होगी। कार्यपद्धति में सुधार होगा। कार्यसिद्धि से प्रसन्नता रहेगी। मेहनत सफल रहेगी। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। मान-सम्मान मिलेगा।

कुम्भ राजकीय सहयोग से कार्य पूर्ण होंगे। व्यापार-व्यवसाय मनोनुकूल लाभ देगा। वैवाहिक प्रस्ताव मिल सकता है। आवश्यक वस्तु समय पर नहीं मिलने से खिन्नता रहेगी।

मीन नवीन वस्त्राभूषण पर व्यय होगा। परीक्षा व साक्षात्कार आदि में सफलता प्राप्त होगी। यात्रा मनोनुकूल लाभ देगी। नए काम मिल सकते हैं। कार्य से संतुष्टि रहेगी।

बॉलीवुड | मन की बात

द केरल स्टोरी के समर्थन में आए अनुराग कश्यप

पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अपने राज्य में द केरल स्टोरी के प्रदर्शित नहीं होने दिया है। राज्य सरकार ने पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए फिल्म पर बैन लगा दिया है। सुदीप्तो सेन के निर्देशन में बनी और अदा शर्मा स्टारर यह फिल्म रिलीज होने के पहले से ही विवादों से घिरी है। वहीं बहुत से लोग द केरल स्टोरी के पक्ष में भी हैं। इस लिस्ट में अब अनुराग कश्यप का नाम भी शामिल हो गया है। निर्देशक ने बिना नाम लिए सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर की है। उन्होंने ने फ्रांसीसी लेखक वोल्टेयर की एक कहावत पोस्ट में साझा की है। अनुराग कश्यप द्वारा साझा किए गए पोस्ट में लिखा था, मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं आपके कहने के अधिकार की मरते दम तक रक्षा करूंगा। आप फिल्म से सहमत हैं या नहीं, यह प्रचार हो, काउंटर प्रोपगंडा, आपत्तिजनक या नहीं, लेकिन इस पर प्रतिबंध लगाना गलत है। अनुराग ने फिल्म निर्माता सुधीर मिश्रा की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म अफवाह का भी सपोर्ट किया और लोगों से देखने के आग्रह किया। फिल्ममेकर में लिखा, आप प्रोपगैंडा से लड़ना चाहते हैं, तो जाकर फिल्म देखें जो सोशल मीडिया के दुरुपयोग के खिलाफ आवाज उठाती है। फिल्म दिखाती है कि निहित पूर्वाग्रह को कैसे नफरत और अशांति पैदा करने के लिए हथियार बनाया जाता है। अनुराग ने कहा कि यह सिनेमाघरों में लगी हुई है और इसका नाम अफवाह है। लड़ने का यही सही तरीका है। द केरल स्टोरी की कहानी केरल की मासूम हिंदू महिला के इर्द-गिर्द बुनी गई है, जिसका इस्लामिक दोस्तों द्वारा ब्रेनवॉश कर दिया जाता है। उसका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। इतना ही नहीं उसे आईएसआईएस आतंकवादी संगठन में भेज दिया जाता है। फिल्म सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित और विपुल अमृतलाल शाह द्वारा निर्मित है। फिल्म सत्या घटना पर आधारित होने का दावा करती है।

फिर धूम मचाएगी एकता और रिया की जोड़ी

एकता कपूर ने रिया कपूर के साथ अपनी अपकमिंग मूवी की अनाउंसमेंट कर दी है। इस मूवी से पहले भी एकता और रिया कपूर ने साथ काम किया हैं। हालांकि अभी तक इस अपकमिंग मूवी का टाइटल कंफर्म नहीं हो पाया है। दोनों ने मिलकर एक बार फिर से दर्शकों को एंटरटेन करने की तैयारी में लग गई है। वहीं फैंस भी फिल्म से जुड़ी अपडेट जानने को हैरान हैं। एकता कपूर और रिया कपूर के इस नए प्रोजेक्ट की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड और अनिल कपूर फिल्म कम्युनिकेशन नेटवर्क के बैनर तले बनने वाली ये मूवी 22 सितंबर 2023 को रिलीज की जाएगी। इसी वजह से मूवी पर काम तेजी से शुरू कर दिया गया है, ताकि फिल्म समय पर पूरी हो सके। रिया कपूर और एकता कपूर अपकमिंग फिल्म तीन औरतों की लाइफ पर फोकस्ड होने वाली है। जैसे-जैसे वे जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं। वैसे ही वैसे उनकी लाइफ बदलने लगती है, और वे सभी झूठ के जाल में फस जाती हैं। बता दें इससे पहले भी दोनों ने वीरे दी वेडिंग की थी, जिसमें भी 4 दोस्तों की कहानी थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी।

भोजपुरी | मसाला

इंतजार खत्म : ऋतिक- सैफ की विक्रम वेधा की ओटीटी पर एंट्री कल

ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की एक्शन थ्रिलर फिल्म विक्रम वेधा ओटीटी पर स्ट्रीम होने जा रही है। फिल्म बीते साल थिएटर्स में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक कमाई की थी।

विक्रम वेधा के ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे फैंस को जियो सिनेमा ने खुशखबरी दी है। फिल्म की रिलीज की जानकारी देते हुए ओटीटी प्लेटफॉर्म ने ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज पर अपडेट शेयर की है। फिल्म 12 मई को स्ट्रीम होगी और बिना सब्सक्रिप्शन विक्रम वेधा को देखा जा सकता है यानी जियो सिनेमा पर फिल्म फ्री में उपलब्ध होगी।

विक्रम वेधा का ट्रेलर शेयर करते हुए जियो सिनेमा ने कैप्शन में लिखा, फ्ढ्ढक्रू में टीम्स की जंग के बीचअब देखो विक्रम वेधा की जंग। इसके साथ स्ट्रीम डेट के बारे में बताते हुए आगे लिखा, शुक्रवार 12 मई को जियो सिनेमा पर विक्रम वेधा का वर्ल्ड डिजीटल प्रीमियर देखिए।

विक्रम वेधा में ऋतिक रोशन और सैफ अली खान के साथ राधिका आप्टे भी अहम किरदार में हैं। फिल्म को गायत्री और पुष्कर जोड़ी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म 30 सितंबर 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। बता दें कि विक्रम वेधा इसी नाम की तमिल फिल्म का हिंदी रीमेक है। ओरिजिनल फिल्म को भी गायत्री और पुष्कर ने डायरेक्ट किया था, जिसमें आर माधवन और विजय सेतुपति लीड रोल में थे। विक्रम वेधा की कहानी की बात करें तो फिल्म ऋतिक रोशन और सैफ अली खान के इर्द-गिर्द घूमती है। विक्रम एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, लेकिन उसकी टीम कर्पट है। वहीं, वेधा एक जाना-माना क्रिमिनल है।

अजब-गजब | इस देश में मास्क ने छीन ली चेहरे की मुस्कुराहट

यहां हंसना भूल गए लोग, मुस्कुराना सीखने के लिए कर रहे कोचिंग

मुस्कुराना जीवन के लिए बहुत जरूरी है। डॉक्टर कहते हैं कि चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान हर बीमारी का इलाज है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा होगा कि मुस्कुराना सीखने के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे? ट्रेनर रखने होंगे, कोचिंग सेंटरों में जाना होगा। शायद नहीं। मगर जापान में ऐसा हो रहा है। वहां के लोग मुस्कुराना भूल गए हैं। अब उन्हें यह सीखना पड़ रहा है और इसके लिए भारी भरकम रकम चुकानी पड़ रही है।

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, कोरोना महामारी की वजह से 3 साल तक लोग मास्क के पीछे चेहरा छिपाकर रहे। पिछले हफ्ते सरकार ने सभी पाबंदियां हटा लीं तो पता चला कि लोग मुस्कुराना भूल गए हैं। उन्हें डर है कि वे इतने लंबे समय से मास्क पहन रहे हैं कि भूल गए हैं कि मुस्कुराना कैसे है। इसके लिए पैसे खर्च कर रहे हैं। एक्सपर्ट रख रहे हैं। कई लोगों को लगता है कि मास्क की वजह से अब उनके चेहरे पर हंसमुख भाव नहीं आ रहे है, इसलिए विशेषज्ञों का रुख कर रहे हैं।

जापान टाइम्स से बात करते हुए, स्माइल

ट्रेनर मिहो किटानो ने कहा-मैंने तमाम लोगों से सुना कि भले ही वे अपना मास्क हटा सकते हैं लेकिन अभी भी वह चेहरे का निचला हिस्सा नहीं दिखाना चाहते। क्योंकि उन्हें डर है कि मुस्कुराकर वह जवाब नहीं दे पाएंगे। कुछ को लगता है कि अगर वे ज्यादा दबाव डालकर मुस्कुराएं भी तो चेहरे पर और आंखों के चारों ओर ज्यादा झुर्रियां नजर आने लगती हैं, इससे वे बुजुर्ग दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि उनका चेहरा लटक गया है। इसलिए वह जबरदस्ती मुस्कुराना नहीं चाहते।

किटानो ने बताया कि उनकी कंपनी स्माइल फेशियल मसल एसोसिएशन का कारोबार इसी वजह से आसमान छूने लगा है। लोग कोविड के पहले जैसा चेहरा और हावभाव देखना चाहते हैं। जब उनसे पूछा गया कि आखिर सेंटर पर होता क्या है? उन्होंने जवाब दिया, स्माइल एक्सपर्ट मुस्कान में मदद करने वाले योगाभ्यास कराती हैं। उन्हें काटने के लिए कुछ चीजें दी जाती हैं ताकि उनके गाल की मांसपेशियों को ऊपर उठाने में मदद मिले। दांत दिखाने में मदद मिले। वह कहती हैं कि मैं कई ऐसे लोगों से मिलती हूं जो मुस्कुराने में अच्छे नहीं हैं, लेकिन उन्हें ठीक किया जा सकता है। उनकी मसल्स को ठीक करना होगा। भुजाओं का व्यायाम कराना होगा।

बर्फ खाकर जिंदा रहा 8 साल का बच्चा 20 डिग्री टेंपरेचर में ऐसे बचाई जान

कोई बर्फीले तूफान में फंस जाए, रास्ता नजर न जाए। आसपास कोई दिखे न, तो क्या हालत होगी समझा जा सकता है। मगर अमेरिका में 8 साल का एक बच्चा -20 डिग्री टेंपरेचर में महज एक वुलेन टीशर्ट पहनकर दो दिन तक जिंदा रहा। प्यास लगी तो बर्फ खाकर प्यास बुझाई। बचने के लिए उसने ऐसी तकरीब अपनाई कि बचाव दल भी देखकर हैरान था। मामला अमेरिका के विस्कॉन्सिन का है। 8 साल का नांटे नीमी परिवार के लिए जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जंगल गया लेकिन वहां रास्ता भटक गया। फिर वह अंदर की ओर चलता चला गया। उसे कुछ भी रास्ता नहीं सूझ रहा था। वह पगडंडियों पर चलता रहा। जब उसे लगा कि वह अब निकल नहीं सकता तो उसने एक छोटी पहाड़ी से नीचे छलांग लगाई। एक ऐसी जगह जाकर छिप गया जहां एक पेड़ था। उस जगह बर्फ बहुत थी और ठंड भी खूब लग रही थी, इससे बचने के लिए बच्चे ने पेड़ों की शाखाएं तोड़ीं। उनसे एक झोपड़ीनुमा घर बनाया। पत्तियों से एक कंबल जैसी चीज तैयार की और उसी से बिस्तर बर्फ खाता था। इन पत्तियों की बदौलत ने उसे -20 डिग्री टेंपरेचर सहन कर लिया। जबकि उसने सिर्फ एक स्वेटशर्ट पहना हुआ था। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने बचाव अभियान शुरू किया। 150 से ज्यादा सुरक्षाकर्मियों आसमान, पानी और पैदल उसे तलाशने निकले। नौ हेलीकॉप्टर्स लगाए गए। लगभग 40 वर्गमील क्षेत्र का कोना कोना तलाशा गया। आखिरकार वह एक लॉग के नीचे छिपकर बैठा हुआ नजर आया। मिशिगन पुलिस ने पहले उसे हेलीकॉप्टर के जरिए बाहर निकालना चाहा लेकिन बच्चे ने कहा कि वह पैदल ही आना चाहता है। आखिरकार वह बाहर आ गया और अभी सुरक्षित है।

शहर की सरकार चुनने निकले लोग, मतदान में लगी लंबी कतार

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नोएडा। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में 38 जिलों में मतदान जारी है। सुबह के समय धीरे-धीरे शुरू हुई वोटिंग दोपहर होते-होते बढ़ने लगी। कई जिलों में लंबी-लंबी कतारें देखी गई। कुछ जगहों झड़प की खबरें भी आई पर मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है।

इस चरण के लिए 370 निकायों के लिए 6929 विभिन्न पदों पर 39146 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन सभी का भाग्य आज ईवीएम और मतपेटिकाओं में बंद होगा। सपा, भाजपा, कांग्रेस सभी जीत का दावा कर रहे हैं।

38 जिलों में हो रही वोटिंग, कई जगह हुई झड़प

मिर्जापुर डीएम ने लाइन में लगकर डाला वोट

मिर्जापुर में जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने नगर निकाय चुनाव में बिसुंदरपुर इंटर कॉलेज के पोलिंग बूथ संख्या 17 पर महिलाओं की लाइन में कतारबद्ध होकर वोट डालने के लिए अपने नंबर का इंतजार किया। वोट डालने के बाद पिंक/महिला बूथ पर सेल्फी प्वाइंट पर सेल्फी भी ली।

भाजपा विधायक का नाम वोटर लिस्ट से गायब

पीलीभीत में मॉडल स्कूल के बाहर वोटर लिस्ट में नाम ना होने पर मतदाता भड़क गए। उन्होंने हंगामा कर दिया। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस और अधिकारी पहुंचे। मतदाताओं का आरोप था कि न पर्ची दी जा रही न वोटर लिस्ट में नाम है। कानपुर में विधायक राहुल सोनकर और उनकी पत्नी का नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गया है। वोटिंग लिस्ट में नाम न होने की वजह से वो मतदान नहीं कर पाए हैं। राहुल सोनकर बिल्हौर विधानसभा से भाजपा विधायक हैं। वोटर लिस्ट में बहुत से लोगों के नाम गायब हैं। कही पर एक ही व्यक्ति का नाम कई बार अंकित किया गया है।

मुस्लिम महिला मतदाताओं की लंबी लाइन

मऊ नगर के सर इकबाल पब्लिक स्कूल बूथ पर मुस्लिम महिला मतदाताओं की लंबी कतार लगी है। मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। मेरठ के रशीद नगर के वार्ड 89 में कुछ वोटरों ने वोटर लिस्ट में नाम नहीं मिलने पर हंगामा कर दिया। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत करा दिया। उधर, शेरगढ़ी में दलित वोटों में बंटवारा हो गया है। अभी तक हुए मतदान के अनुसार, हाथी को छोड़कर मतदाता साइकिल पर सवार होकर दौड़ रहे हैं।

मेरठ में आप और भाजपा समर्थक में मारपीट

मेरठ में मोदीपुरम स्थित डीएमए स्कूल में आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी ऋचा सिंह ने भाजपा समर्थकों पर मनमानी का आरोप लगाया। इस बीच भाजपा कार्यकर्ताओं की आप पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बहस हुई। ऋचा सिंह ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता पुलिस के साथ भी बहस कर रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने उच्च अधिकारियों से भी शिकायत की। ऋचा सिंह ने बताया कि फतेहउल्लापुर में भी गड़बड़ी की शिकायत मिल रही हैं। वहीं कानपुर में वार्ड 70 के प्रत्याशी पुत्र के अश्लील फोटो वायरल हुए हैं। शिवबालक राजपूत के पुत्र सौरभ राजपूत के अश्लील पोस्टर चस्पा हुए हैं। लड़की के साथ अश्लीलता करते हुए पोस्टर चस्पा हुए हैं। वार्ड 70 में कई जगह शिवबालक के पुत्र सौरभ राजपूत के अश्लील पोस्टर चस्पा किए गए हैं। घंटी वाले प्रत्याशी के पुत्र की घिनौनी तस्वीरों वाले पोस्टर चस्पा किए गए हैं।

फर्रुखाबाद : वोट डालने के बाद वृद्धा की मौत

फर्रुखाबाद के कायमगंज की मोहल्ला नुनहाई निवासी घासीराम की 75 वर्षीय पत्नी रेशमा देवी कन्या विद्या पीठ मतदान केंद्र पर परिजनों के साथ मतदान करने पहुंची। मतदान करने के बाद वृद्धा बाहर निकलते समय गश खाकर गिर गई। अचानक महिला के गिरने से वहां भगदड़ मच गई। वृद्धा को सीएचसी ले जाया गया। जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।

एक बार फिर दहला अमृतसर आरोपी गिरफ्तार

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

चंडीगढ़। पंजाब के अमृतसर को दहलाने की साजिश रची जा रही है। बुधवार देर रात श्री गुरु रामदास सराय के पीछे हुए धमाके के आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ये बड़ा खुलासा हुआ है। खुफिया सूत्रों के अनुसार, आरोपियों के पास और भी कई बम थे। अब पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। आरोपियों की पहली तस्वीर भी सामने आ गई हैं। सराय की सीसीटीवी फुटेज में दो आरोपी दिखे हैं। धमाके के बाद दोनों सराय में आकर सो गए थे। एसजीपीसी के कर्मचारियों ने दोनों को पकड़ा।

धमाके से सहमे लोग कई बम भी बरामद

बुधवार-गुरुवार देर रात करीब 12 बजकर 40 मिनट पर स्वर्ण मंदिर के पास श्री गुरु रामदास सराय के पिछली तरफ गलियारे में जोरदार धमाका हुआ था। पांच दिनों में श्री हरमंदिर साहिब के पास यह तीसरा धमाका हुआ है। धमाका इतना जोरदार था कि इसकी आवाज तीन सौ मीटर दूरी तक सुनाई दी। यह धमाका पहले दो धमाकों वाली बिल्कुल विपरीत दिशा में है, जो पहले हेरिटेज स्ट्रीट में हुए धमाकों से करीब एक किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। बम धमाके के मामले को सुलझाते हुए पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। डीजीपी गौरव यादव ने इसकी पुष्टि की है।

एनआईए और एनएसजी कर रही है जांच

इससे पहले शनिवार की देर रात और सोमबार की सुबह हेरिटेज स्ट्रीट में स्थित सारागढ़ी सराय के पास धमाके हुए थे। दोनों मामलों में जहां पंजाब पुलिस फोरेंसिक विभाग सैंपल लेकर जांच कर रही है वहीं एनआईए और एनएसजी ने घटनास्थल का दौरा कर धमाके का सीन रिक्रिएट कर वहां से मिट्टी और पत्तों के सैंपल जुटाने के बाद उन्हें जांच के लिए भेजा है, जिनकी पुलिस और एजेंसियों को रिपोर्ट का इंतजार है।

बैंक डिफाल्टर घोषित हुआ महाठग शेरपुरिया

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। महाठग संजय शेरपुरिया को आईडीबीआई बैंक ने डिफाल्टर घोषित कर दिया है। शेरपुरिया ने कांडला एनर्जी एंड केमिकल लि. कंपनी को संचालित करने के लिए 39.72 करोड़ का बैंक से कर्ज लिया था। रकम लेने के बाद उसने एक रुपये भी वापस नहीं किया।

एसटीएफ के सूत्रों के मुताबिक शेरपुरिया ने यह कर्ज 2005 में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (आईडीबीआई) से लिया था। शेरपुरिया की गिरफ्तारी के पांच दिन बाद 30 अप्रैल को डिफाल्टरों की सूची जारी की। जिसमें 73वें स्थान पर संजय बालेश्वर राय का नाम विलफुल डिफाल्टर की लिस्ट में दर्ज है।

इस मामले में आईडीबीआई ही कंसोर्टियम बैंक है। एसटीएफ के मुताबिक कर्ज की रकम हासिल करने के बाद शेरपुरिया ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। जिस कंपनी के नाम पर यह लोन लिया गया था, उसमें शेरपुरिया और उसकी पत्नी कंचन राय भी बतौर निदेशक शामिल हैं। उसे दिवालिया घोषित करने के बाद बैंक ने कागजी कार्रवाई के बाद उसे डिफाल्टर की सूची में डाला है।

माही की टीम प्लेऑफ के करीब

चेन्नई की सीजन की सातवीं जीत, सुपरकिंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 27 रनों से हराया

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

चेन्नई। आईपीएल के 55वें मुकाबले में चेन्नई सुपरकिंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 27 रन से हरा दिया। दोनों टीमें एमए चिदंबरम स्टेडियम में आमने-सामने हुईं। चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। चेन्नई ने 20 ओवर में आठ विकेट पर 167 रन बनाए। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की टीम 20 ओवर में आठ विकेट पर 140 रन ही बना सकी। गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर चेन्नई सुपरकिंग्स ने आईपीएल के मौजूदा सीजन में सातवीं जीत हासिल कर ली। उसने इस जीत के साथ ही प्लेऑफ के करीब खुद को पहुंचा दिया है।

उसके 12 मैचों में अब 15 अंक हो गए। दूसरी ओर, दिल्ली कैपिटल्स की 11 मैचों में यह सातवीं हार है। उसके आठ अंक ही हैं। दिल्ली का अगला मुकाबला 13 मई को पंजाब किंग्स से होगा। वहीं, चेन्नई की टीम 14 मई को कोलकाता के खिलाफ उतरेगी।

मथीश पथिराना ने तीन और दीपक चाहर ने दो विकेट लिए। रवींद्र जडेजा को एक सफलता मिली। चेन्नई के चार गेंदबाजों ने आठ से ज्यादा की इकोनॉमी रेट से रन नहीं दिए। सबने मिलकर दिल्ली के बल्लेबाजों को बांधे रखा। इसका फायदा टीम को हुआ और उसने जीत की हैट्रिक लगाई।

दिल्ली के बल्लेबाजों ने किया निराश

दिल्ली के बल्लेबाजों की बात करें तो किसी ने अर्धशतक नहीं लगाया। रिले रूसो ने सर्वाधिक 35 रन बनाए। मनीष पांडे और अक्षर पटेल 21 रन बनाकर आउट हुए। फिलिप साल्ट ने 17, ललित यादव ने 12 और रिपल पटेल ने 10 रन बनाए। कप्तान डेविड वॉर्नर खाता नहीं खोल सकीं। मिचेल मार्श पांच और अमन हकीम खान दो रन ही बना सके। दिल्ली कैपिटल्स को 13वें ओवर की आखिरी और 15वें ओवर तीसरी गेंद पर क्रमश : चौथा और पांचवां झटका लगा। पथिराना ने मनीष पांडे को एलबीडब्ल्यू कर दिया। पांडे 29 गेंद पर 27 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने एक चौका और दो छक्के लगाए। उनके बाद रिले रूसो भी पवेलियन लौट गए। रूसो 37 गेंद पर 35 रन बनाकर आउट हुए। जडेजा की गेंद पर पथिराना ने उनका कैच लिया।

एटा में कबाड़ी की दुकान में घुसी स्कॉर्पियो, चार की मौत

एटा। एटा के थाना पिलुआ के पास बृहस्पतिवार की सुबह करीब सात बजे स्कॉर्पियो कार कबाड़ी की दुकान में घुस गई। तेज रफ्तार होने के चलते मौके पर ही तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक ने जिला अस्पताल लाते समय दम तोड़ दिया। दो लोगों को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। मृतकों के नाम और पते अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं। कार में सवार घायल बोलने की स्थिति में नहीं हैं, इसके चलते स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि मृतक और घायल कहां के रहने वाले हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। घायलों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

Contact for
Grills, Railing, Gate, Tin Shade, Stairs and other fabrication

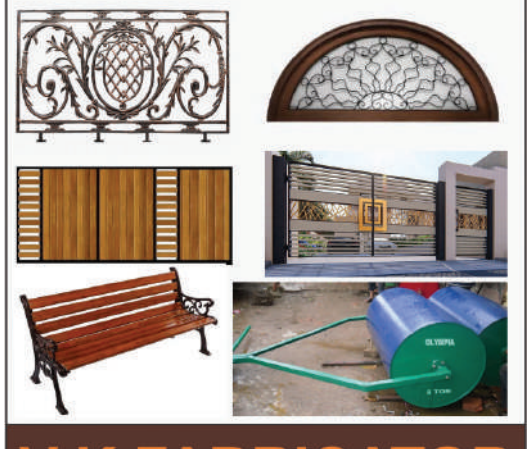

V K FABRICATOR
5/603 Vikas Khand, Gomti Nagar Lucknow -226010
Mob : 9918721708

कर्नाटक में लग सकता है भाजपा को करारा झटका

एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बनने का अनुमान, 10 पोल्स में से 4 में कांग्रेस को बढ़त, 1 पोल भाजपा को दे रहा है बहुमत

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

बेंगलुरु/नई दिल्ली। सांप, नालायक, बजरंग दल बैन से लेकर बजरंगबली की जय और चुनाव आयोग तक पहुंचे कर्नाटक की संग्रभुता जैसे बयान खत्म। कर्नाटक की 224 सीटों पर वोटिंग भी पूरी। वोट 72.67 प्रतिशत पड़े। अब इंतजार रिजल्ट का। पर उससे पहले एग्जिट पोल। इस बार 10 पोल्स में से 4 में कांग्रेस की सरकार बन रही है। 1 पोल भाजपा को बहुमत दे रहा है। 5 सर्वे में हंग असेंबली है।

जेडीएस को 21 से 28 सीट के साथ 4 सर्वे किंगमेकर बता रहे। यानी 2018 की तरह एक बार फिर जेडीएस के बिना कांग्रेस या भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक भाजपा 91, कांग्रेस 108, जेडीएस 22 और अन्य को 3 सीट मिलने का अनुमान है।

2018 में 6 बड़े एग्जिट पोल में से 4 में भाजपा को सबसे बड़ी पार्टी बताया गया था। ये सही रहा। भाजपा 224 में से 104 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। पर कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर सरकार बनाई। उठापटक जारी रही। 5 साल में कर्नाटक ने 2 सरकारें और 3 मुख्यमंत्री देखे।

पोल ऑफ पोल्स

भाजपा— 91
कांग्रेस— 108
जेडीएस— 22
अन्य — 03

पांच सर्वे में हंग असेंबली की ओर इशारा

इंडिया टीवी-सीएनएक्स: किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं

पोल के मुताबिक, कांग्रेस 105 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। भाजपा 85 और जेडीएस 32 सीटें जीत सकती है। यानी बहुमत किसी को नहीं। सर्वे 6 मई को हुआ था। इसमें 112 सीटों के 11 हजार 200 लोगों से बातचीत की गई थी।

एबीपी न्यूज़-सी वोटर
कांग्रेस की सरकार

सर्वे में कांग्रेस को 110 से 122, भाजपा को 73 से 85 और JDS को 21 से 29 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी सरकार कांग्रेस की। सर्वे में 73 हजार लोगों का फीडबैक है। 44% लोगों ने कांग्रेस की, 32 प्रतिशत ने भाजपा की सरकार बनने का अनुमान जताया। 31 प्रतिशत लोगों ने बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बताया।

जी न्यूज़-मैट्रिज
कांग्रेस की बढ़त

सर्वे में कांग्रेस को 103 से 118, भाजपा को 79 से 94 और जेडीएस को 25 से 33 सीटें मिलने का अनुमान। सैंपल साइज के लिहाज से यह सबसे बड़ा ओपिनियन पोल है। इसमें 224 सीटों पर 3 लाख 36 हजार लोगों से सवाल किए गए। हर विधानसभा सीट पर 1500 लोगों से बात की गई।

शरद पवार के करीबी जयंत पाटिल को ईडी का नोटिस

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

कल होना होगा पेश

मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी(राकांपा) की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष एवं विधायक जयंत पाटिल को धनशोधन मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा है। जयंत पाटिल, शरद पवार के करीबी माने जाते हैं,उन्हें ईडी ने शुक्रवार (12 मई) को पेश होने को कहा है।

पाटिल से आईएल एंड एफएस मामले में पूछताछ होनी है। जांच एजेंसी ने पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे से कोहिनूर कंस्ट्रक्शन को दिए गए ऋण के मामले में पूछताछ की, जो मुंबई के दादर में कोहिनूर स्क्वायर टॉवर का विकास कर रही है। बीएसआर और एसोसिएट्स, लेखा फर्म केपीएमजी के एक भारतीय सहयोगी और डेलॉइट हास्किन्स एंड सेल्स के खिलाफ छापेमारी के बाद आया है। जांच एजेंसी ने आईएल एंड एफएस पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया है। आईएल एंड एफएस के पूर्व लेखा परीक्षकों के खिलाफ जांच एजेंसी की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट के एक फैसले को रद्द करने के बाद हुई थी, जिसमें दोनों फर्मों के खिलाफ जांच रद कर दी गई थी।

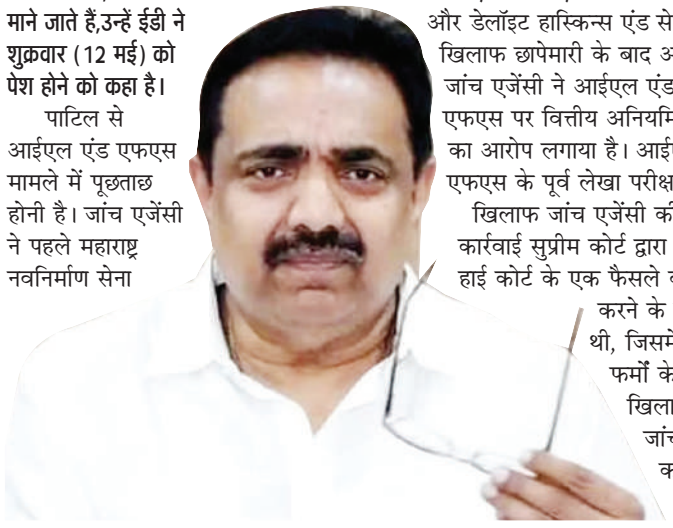

पायलट ने शुरू की जनसंघर्ष पदयात्रा अजमेर से जयपुर तक जाएंगे

भ्रष्टाचार और पेपर लीक के मुद्दे पर कर रहे यात्रा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

जयपुर। प्रदेश में अपनी ही कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और पेपर लीक के मुद्दे पर जन संघर्ष पदयात्रा निकाल रहे सचिन पायलट को आतंकी हमले का खतरा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजस्थान के डीजीपी को एक गोपनीय पत्र भेजकर कड़े सुरक्षा बंदोबस्त करने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक, सीआरपीएफ की एक बटालियन के काफी सारे जवान पायलट की सुरक्षा के लिए अजमेर भेज दिए गए हैं।

पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की आज 11 मई से 15 मई तक होने वाली जन संघर्ष पदयात्रा को सीआरपीएफ का सुरक्षा कवर मिलेगा। बड़ी संख्या में वर्दी में और सादे वस्त्रों में जवान तैनात रहेंगे। जो सचिन पायलट के साथ-साथ पदयात्रा में चलेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से 11 मई से 15 मई तक का सचिन पायलट का पूरा शेड्यूल डीजीपी राजस्थान और डीजीपी आरपीएफ को भेजा है। राजस्थान पुलिस के आईजी सिक्योरिटी, पुलिस कमिश्नर जयपुर और अजमेर पुलिस एसपी को भी लेटर जारी किया गया है।

पायलट के लिए अतिरिक्त सुरक्षा के बंदोबस्त

पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को वाई कैटेगरी की सीआरपीएफ की सुरक्षा केंद्र सरकार से देश भर में प्राप्त है। राजस्थान पुलिस डीजीपी और तमाम संबंधित आला पुलिस अधिकारियों को सचिन पायलट की सुरक्षा को लेकर सीआरपीएफ का पूरा सहयोग करने को कहा गया है। पत्र में कहा गया है कि सचिन पायलट की सुरक्षा को कई आतंकी संगठनों से थ्रेट है। इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए जाएं। डीजीपी आरपीएफ को भी पायलट की रेल यात्रा की सुरक्षा को कहा गया है।

पाकिस्तान के पंजाब और खैबर में सेना तैनात

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

इस्लामाबाद। भ्रष्टाचार के आरोप में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में हालात बेकाबू हो रहे हैं। इमरान की गिरफ्तारी के एक दिन बाद पाकिस्तान के कई शहरों में हिंसा भड़की और हालात तनावपूर्ण रहे। पिछले 24 घंटे के दौरान कई शहरों में इमरान खान के समर्थकों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पों में कम-से-कम सात लोगों की मौत हो गई और लगभग 300 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में इमरान की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने पंजाब में 14 सरकारी भवनों और प्रतिष्ठानों में आग लगा दी। उन्होंने 21 पुलिस वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया।

अब तक आठ लोगों की मौत

इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) समर्थकों के साथ झड़प में 130 अधिकारी और सुरक्षा बलों के कर्मचारी घायल हो गए। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पंजाब, खैबर-पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सेना तैनात की गई है। राजधानी इस्लामाबाद में भी सेना को उतार दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने लाहौर में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के आवास पर हमला कर दिया। पुलिस के अनुसार, 500 से अधिक प्रदर्शनकारी बुधवार तड़के प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे और वहां रखे वाहनों को फूंक दिया। आवासीय परिसर में उन्होंने पेट्रोल बम फेंका और पुलिस बूथ को आग के हवाले कर दिया।

समर्थक देशभर में कर रहे विरोध प्रदर्शन

इमरान की गिरफ्तारी से नाराज समर्थकों ने मंगलवार को सेना मुख्यालय पर धावा बोल दिया था। उन्होंने सैन्य वाहनों और प्रतिष्ठानों पर हमला करते हुए लाहौर कोर कमांडर के आवास में आग लगा दी थी। पीटीआइ ने गिरफ्तारी की निंदा करते हुए बुधवार को राटष्ट्रव्यापी हड़ताल का एलान किया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के समर्थकों ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ वाशिंगटन में पाकिस्तान दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इमरान खान की रिहाई की मांग की और यहां तक कि मुख्य न्यायाधीश और सेना के जनरलों के खिलाफ नारे भी लगाए।

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक **बबिता चतुर्वेदी** के लिए **4पीएम** आस्था प्रिंटर्स, 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (यूपी) से मुद्रित एवं प्रकाशित। **प्रधान संपादक**- अर्चना दयाल, **संपादक** - संजय शर्मा, **विधि सलाहकार**: सत्यप्रकाश श्रीवास्तव, मोहम्मद हैदर, **वित्तीय सलाहकार**: संदीप बंसल, **कार्टूनिस्ट**: हसन जैदी, **दूरभाष**: 0522- 4078371 | **Email**: daily4pm@gmail.com | **website**: www.4pm.co.in | **RNI-UPHIN/2015/62233** डाक पंजी. सं- SSP/LW/NP-495/2018-2020
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय के अधीन ही होंगे।